pending completion and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV A): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

BICP recommendations with regard to sugar industry

2100. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the Centre has examined the report of Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) to facilitate the reworking of the Licencing Policy for sugar sector;

(b) what are the salient features in the BICP recommendations in regard to fixing of free sale quota in high recovery areas and exemption of levy on expanded capacity; and

(c) the reaction of Indian Sugar Mills Association (ISMA) and National Federation of Cooperative Sugar Factories in this regard?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) Ministry of Food has recently received a Report on Sugar Incentive Scheme from the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) for grant of incentives for new and expansion projects licensed/to be licensed during the period from 01-04-1994 to 31-03-1997. The Report is under examination.

विदेशी क्रेताओं को घटिया माल की आपूर्ति

2101. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान घटिया स्तर की वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने के संबंध में क्रेताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(क) शिकायतें मुख्य रूप से सहमत उत्पाद विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने और खाद्य मदों जल्दी खराब होने वाली मदों में खराबी अथवा प्रदूषण के बारे में थी।

(ख) गुणवत्ता शिकायतों संबंधी क्षेत्रीय स्थायी समितियों का गठन अहमदाबाद, बंबई, बंगलौर, कलकत्ता, कोचीन दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना और मद्रास में किया गया हैं जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करती हैं। इन समितियों ने वर्ष 1994-95 में इस प्रकार की 66 शिकायतों का निपटान किया। वर्ष 1994-95 के दौरान 20 निर्यातकों के विरूद्व विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की गई और 9 मामलों में वित्तीय दण्ड वर्जन आयातक-निर्यातक कोड संख्या का निरसन, आदि की कार्यवाहियों के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2102. **श्री मूलचन्द मीणा** :

श्री अजीज जोगी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का विचार हैं;

(ख) इस विशेष योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के बाद अब तक कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जा चुका हैं; और

(ग) सरकार चालू वर्ष के दौरान इन प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के खोले जाने की संख्या निम्नलिखित हैं :- आन्ध्र प्रदेश-13, असम-3, गुजरात-4 , हरियाणा-5, केरल-5, मध्य प्रदेश-10, उत्तर प्रदेश-9

पश्चिम बंगाल-4, महाराष्ट्र-9, बिहार-8, कर्नाटक-10, तमिलनाडु-5, राजस्थान-4, उड़ीसा-6 तथा पंजाब-5, संघ शासित प्रदेश- कोई नहीं।

(ख) और (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा प्राप्त संगत कौशलों के अनुरूप मजदूरी रोजगार या स्व-रोजगार स्वयं प्राप्त करने होते हैं। योजना के अंतर्गत, सरकार उन्हे रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्व/बाध्य नहीं हैं, जिन्होने प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात का लक्ष्य

2103. **श्री अजीत जोगी** :

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वाणिज्य मंत्री 4 दिसंबर,1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 114 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) वर्ष 1995—96 के दौरान किन-किन मदों के आयात और निर्यात में वृद्वि हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इन निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) 1995-96 के दौरान अप्रैल-सिंतबर , 95 की अवधि जिसमें व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान जिन मुख्य मदों के आयातों में वृद्वि हुई, उनमें खाद्य तेल, उर्वरक, अलौह धातुएं, मशीनरी, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर, अखबारी कागज, सिन्थेटिक और पुनः तैयार किए गए रेशे, इलेक्ट्रानिक सामान, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, पेपर बोर्ड और उनके उत्पाद, परियोजना माल, व्यावसायिक उपकरण तथा धातु के उत्पाद शामिल हैं; इसी अवधि के दौरान जिन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्वि हुई उनमें चाय और काफी सहित कृषि एवं सम्बद्व उत्पाद अयस्क एवं खनिज, हस्तशिल्प सहित वस्त्र इलेक्ट्रानिक्स, रसायन और संबद्व उत्पाद, इंजीनियरी वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, खेलकूद का सामान तथा चमड़ा और उसके उत्पाद हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991-92 की कीमतों और विनिमय दरों पर मात्रा के रूप में 13.62 प्रति वर्ष की निर्यात वृद्वि की कल्पना की गई हैं। पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के अंत में कुल निर्यात 33.35 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान हैं।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया हैं। व्यापार, उद्योग तथा अन्य सम्बद्व संस्थानों के साथ परामर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार नीति एंव क्रियाविधियों के वातावरण को निर्यात के लिए और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति एवं क्रियाविधियों का सरलीकरण निर्यात उत्पादन में वृद्वि, कार्यक्षमता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता सुधार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने का उल्लेख किया जा सकता हैं। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्य-योजना तैयार की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु-विशिष्ट और देश-विशिष्ट उपाय आते हैं।

Decline in pcr-capita income of Super Bazar

2104. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the per-capita income in the Super Bazar Sector has registered a sharp decline during the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) the measures proposed to be taken to increase the per-capita income during the Eighth Plan period; and

(d) the amount earmarked for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) Super Bazar has reported that per capita sale, gross profit